



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 27 दिसम्बर, 2006/00 अग्रहायण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-2, 27 दिसम्बर, 2006

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-60/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 31) जो आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने

हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में बल प्रयोग या उत्प्रेरणा द्वारा या कपटपूर्ण साधनों द्वारा संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता संक्षिप्त नाम । अधिनियम, 2006 है ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न परिभाषाएं हो,-

(क) "संपरिवर्तन" से एक धर्म का त्याग करना तथा दूसरे को अपनाना अभिप्रेत है;

(ख) "बल" के अन्तर्गत बल का प्रदर्शन या क्षति की धमकी या देवी अप्रसाद या सामाजिक बहिष्कार की धमकी आएगी;

(ग) "कपट" के अन्तर्गत दुर्व्यपदेशन या अन्य कपटपूर्ण प्रयुक्ति आएगी;

(घ) "उत्प्रेरणा" के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के दान या परितोषण की, या तो वस्तुरूप में या नकद में प्रस्थापना करना या किसी भी प्रकार की प्रसुविधा, चाहे धन सम्बन्धी हो या अन्यथा, देना आएगा; और

(ङ) "अव्यस्क" से अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अभिप्रेत है ।

बलपूर्वक

संपरिवर्तन का
प्रतिषेध ।

3. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्षतः या अन्यथा किसी भी व्यक्ति को, बल प्रयोग द्वारा या उत्प्रेरणा द्वारा या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में न तो संपरिवर्तित करेगा न ही इसका प्रयत्न करेगा न ही कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी संपरिवर्तन को दुष्प्रेरित करेगा ।

धारा 3 के
उल्लंघन के
लिए दण्ड ।

4. कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह, किसी भी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु यदि अपराध किसी अव्यस्क, किसी महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की बाबत किया गया है तो कारावास का दण्ड तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

अपराध का
संज्ञेय होना ।

5. इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा तथा इसका अन्वेषण पुलिस निरीक्षक से नीचे की पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा ।

अभियोजन
जिला
मजिस्ट्रेट की
मंजूरी से
होगा ।

6. इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अभियोजन, जिला मजिस्ट्रेट या ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो उपमण्डल अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे उस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत किया जाए, की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा ।

नियम बनाने
की शक्ति ।

7. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा, राज्य सरकार से बल तथा प्रलोभन पर आधारित धर्म के संपरिवर्तन को नियन्त्रित करने हेतु लगातार मांग की जाती रही है। यह भी देखा गया है कि प्रलोभनों पर आधारित संपरिवर्तनों में सामान्यतः वृद्धि हुई है और यदि समय रहते रोकथाम न की गई तो कहीं यह चलन राज्य में विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के बीच भरोसे और पारस्परिक विश्वसनीयता को समाप्त न कर दे। अतः राज्य में बलपूर्वक धर्म के संपरिवर्तन की रोकथाम करने और राज्य में शांतिमय वातावरण को बनाए रखने हेतु विधान लाने का विनिश्चय किया गया।

; g f d mi; q r m n n b; k d h i f Z d s f y , g S A

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख 2006

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 7 राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतन्त्रता विधेयक, 2006

किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में बल प्रयोग या उत्प्रेरणा द्वारा या कपटपूर्ण साधनों द्वारा संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

वीरमंद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

डॉ० जे० एन० बारोवालिया,
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख, 2006.

Bill No. 31 of 2006.

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for prohibition of conversion from one religion to another by the use of force or inducement or by fraudulent means and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act, 2006. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

Definitions.

- (a) “conversion” means renouncing one religion and adopting another;
- (b) “force” shall include show of force or threat of injury or threat of divine displeasure or social ex-communication ;
- (c) “fraud” shall include misrepresentation or any other fraudulent contrivance ;
- (d) “inducement” shall include the offer of any gift or gratification, either in cash or in kind or grant of any benefit either pecuniary or otherwise ; and
- (e) “minor” means a person under eighteen years of age.

3. No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any person from one religion to another by the use of force or by inducement or by any other fraudulent means nor shall any person abet any such conversion.

Prohibition of forcible conversion.

Punishment
for contra-
vention of
the
provision of
section 3.

4. Any person contravening the provisions contained in section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punishable with imprisonment of either description which may extend to two years or with fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both :

Provided that in case the offence is committed in respect of a minor, a woman or a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, the punishment of imprisonment may extend to three years and fine may extend to fifty thousand rupees.

Offence to be
cognizable.

5. An offence under this Act shall be cognizable and shall not be investigated by an officer below the rank of an Inspector of Police.

Prosecution
to be made
with the
sanction of
District
Magistrate.

6. No prosecution for an offence under this Act shall be made without the sanction of the District Magistrate or such other authority, not below the rank of a Sub-Divisional Officer, as may be authorized by him in that behalf.

Power to
make rules.

7. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rules should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been a persistent demand from across the different strata of the Society, urging the State Government to curb the conversion of religion based on force or allurements. It has also been observed that there is a rise in conversions based on allurements generally and unless checked well in time, this practice may erode the confidence and mutual trust between the different ethnic and religious groups in the State. Thus, in order to check forcible conversion of religion in the State and to preserve the peaceful atmosphere in the State, it has been decided to bring a legislation.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Shimla:

Dated.....,2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 7 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the provisions of this Act. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH FREEDOM OF RELIGION BILL, 2006

A

BILL

to provide for prohibition of conversion from one religion to another by the use of force or inducement or by fraudulent means and for matters connected therewith or incidental thereto.

VIRBHADRA SINGH,*Chief Minister.*

Dr. J. N. BAROWALIA,
Secretary (Law).

Shimla-171002.

The.....2006.